



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1

PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 337]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 21, 2001/अग्रहायण 30, 1923

No. 337]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 21, 2001/AGRAHAYANA 30, 1923

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

सार्वजनिक सूचना

नई दिल्ली, 21 दिसम्बर, 2001

सं. 57 (आर ई-2001)/1997—2002

फा. सं. 01/94/180/051/एएम 02/पीसी-4.—का. आ. सं. 283(अ) दिनांक 31-03-1997 के द्वारा भारत के राजपत्र असाधारण भाग-II, खण्ड-3, उप-खण्ड (ii) में यथाअधिसूचित निर्यात और आयात नीति के पैराग्राफ 4.11 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महानिदेशक, विदेश व्यापार प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड 1), (आर ई 01), 1997—2002 में एतद्वारा निम्नलिखित संशोधन करते हैं :—

(1) पैरा 7.51 के अन्तिम पैराग्राफ को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है:

गुम हुए शिपिंग बिल के मद्दे दावा शिपिंग बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख से 6 महीनों की अवधि के भीतर करना होगा और उसके बाद प्राप्त किसी भी आवेदन को अस्वीकार कर दिया जाएगा। तथापि, यदि तदर्थ तौर पर मूल्यांकित शिपिंग बिल गुम होता है तो डी ई पी बी हेतु आवेदन प्रस्तुत करने की समयावधि शिपिंग बिल के जारी होने/अन्तिम मूल्यांकन की तारीख से 6 माह होगी।

(शिपिंग बिल की गुम हुई ई पी प्रति के मामले में डी ई पी बी/डी एफ आर सी हेतु आवेदन की प्रस्तुति के लिए यह संशोधन प्रमुखतः “निर्यात की तारीख से छह माह” से “शिपिंग बिल की डुप्लीकेट प्रति जारी होने की तारीख से छः माह” तक समयावधि का विस्तार करता है)

(2) एक नया पैरा 10.11 (ख) निम्नानुसार जोड़ा जाता है:

सीमाशुल्क अधिसूचना सं 17 दिनांक 1.3.2001 की सूची 35 की क्रम सं. 370 में विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजना को स्थापित करने हेतु अपेक्षित माल की आपूर्ति जिसकी

क्षमता 440 मेगावाट या अधिक हो और जो भारत सरकार, परमाणु ऊर्जा विभाग के किसी अधिकारी, जिसका स्तर संयुक्त सचिव से कम न हो, द्वारा यथाप्रमाणित हो यह परियोजना उन मामलों में मान्य निर्यात लाभों की पात्र होगी यहाँ प्रतिस्पर्धात्मक बोली (और अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धात्मक बोली नहीं) का अनुसरण किया गया हो ।

ऐसे नाभिकीय ऊर्जा संयंत्रों को आपूर्ति कर रहे घरेलू आपूर्तिकर्ता निर्यात-आयात नीति के पैराग्राफ 10.3 (क), (ख) और (ग), में उल्लिखित लाभों, जो भी मान्य हो, के पात्र होंगे ।

(यह नया पैरा विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को की जानेवाली घरेलू आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभ प्रदान करता है)

(3) “परियोजना प्राधिकारी प्रमाणपत्र का प्रपत्र” से संबंधित परिशिष्ट 98 ‘क’ में निम्नलिखित उप पैरा (छ) को जोड़ा जाता है ।

(छ) प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के अधीन विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को माल की आपूर्ति प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), 1997-2002 के पैरा 10.11 (ख) के प्रावधानों के अनुसार की जाती है और आदेश में आयात अंश रु. (अंकों और शब्दों में.....)

(यह नया पैरा विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को की जानेवाली घरेलू आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभ प्रदान करता है)

(4) ‘परियोजना प्राधिकारी द्वारा जारी भुगतान प्रमाणपत्र का प्रपत्र’ से संबंधित परिशिष्ट 14 ख में निम्नलिखित उप पैरा (vi) जोड़ा जाता है ।

(vi) प्रतिस्पर्धात्मक बोली की प्रक्रिया के तहत विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को माल की आपूर्ति जिसमें वित्त मंत्रालय घरेलू आपूर्तियों के लिए मान्य निर्यात लाभों को उपलब्ध करवाता है ।

(यह नया पैरा विनिर्दिष्ट नाभिकीय ऊर्जा परियोजनाओं को की जानेवाली घरेलू आपूर्तियों को मान्य निर्यात लाभ प्रदान करता है)

इसे लोकहित में जारी किया जाता है ।

एन. एल. लखनपाल, महानिदेशक, विदेश व्यापार

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

PUBLIC NOTICE

New Delhi, the 21st December, 2001

No. 57 (RE-2001)/1997—2002

F. No. 01/94/180/051/AM 02/PC-IV.—In exercise of powers conferred under Paragraph 4.11 of the Export and Import Policy 1997—2002, as notified in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) vide S. O. No. 283(E) dated 31-03-1997, the Director General of Foreign Trade hereby makes the following amendment in Handbook (Vol. 1). (RE-01), 1997—2002.

- 1) The last paragraph of para 7.51 is amended as under:

The claim against the lost Shipping Bill shall be made within a period of six months from the date of issuance of the duplicate copy of the shipping bill and any application received thereafter shall be rejected. Provided however that if a provisionally assessed DEPB shipping bill is lost, the time period for filing of application for DEPB would be 6 months from the date of release / final assessment of the shipping bill.

(This amendment primarily extends the time period for the filing of application for DEPB/ DFRC in the case of lost EP copy of the shipping bill from "six months of the date of export" to "six months from the date of issuance of the duplicate copy of the shipping bill")

- 2) A new para 10.11 (B) is added as under:

Supply of goods required for setting up of any nuclear power project specified in List 35 to S.No 370 of the Customs Notification No 17 dtd 01.03.2001 having a capacity of 440 MW or more, as certified by an officer not below the rank of Joint Secretary to the Government of India in the Department of Atomic Energy, shall be entitled for deemed export benefits in cases where the procedure of Competitive Bidding (and not International Competitive Bidding) has been followed.

The domestic supplier supplying to such nuclear power plants shall be entitled for the benefits listed in paragraph 10.3 (a), (b) and (c) of the Exim Policy, whichever is applicable .

(This new para confers deemed export benefits to domestic supplies to specified nuclear power projects)

- 3) The following sub para (g) is added in Appendix 14 A pertaining to the "Format of the Project Authority Certificate"

(g) That supply of goods to specified nuclear power projects under the procedure of Competitive Bidding in made in accordance with the provisions of para 10.11(B) of Handbook of Procedures (Vol 1), 1997-2002 and the import content of the order is Rs. (Figures and words)

(This new para confers deemed export benefits to domestic supplies to specified nuclear power projects)

4) The following sub para (vi) is added in Appendix 14 B pertaining to the "Format of Certificate of Payments issued by the Project Authority

(vi) Supply of goods to specified nuclear power projects under the procedure of Competitive Bidding in which the Ministry of Finance extends the benefits of deemed exports to domestic supplies.

(This new para confers deemed export benefits to domestic supplies to specified nuclear power projects)

This issues in public interest.

N.L. LAKHANPAL, Director General of Foreign Trade